

पूर्ण न्यायपीठ

माननीय न्यायमूर्ति डी. के. महाजन, बल राज तुली और प्रेम चंद जैन, के समक्ष

मेसर्स पंजाब खांडसारी उद्योग, सोनीपत- याचिकाकर्ता।

बनाम।

राज्य, - उत्तरदाता।

। ' 1970 का सामान्य बिक्री कर संदर्भ 9।

25 अप्रैल, 1972

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1948 का XLVI) - धारा 5 (2) (ए) (ii), दूसरा परंतुक - पंजाब सामान्य बिक्री कर नियम (1949) - नियम 26 - खांडसारी, एक कर-मुक्त वस्तु के निर्माण के लिए, गुड़ को कर-मुक्त खरीदना - नियम 26 के तहत दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर की गई ऐसी खरीद - डीलर का उपयोग करना। केवल खांडसारी के निर्माण के लिए गुड़ - क्या गुड़ की खरीद पर बिक्री-कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है - धारा 5 (2) (ए) (ii) का दूसरा परंतुक - क्या लागू है।

अभिनिर्धारित किया कि जहां कोई डीलर पंजाब सामान्य बिक्री कर नियम 1949 के नियम 26 के तहत दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर कर मुक्त गुड़ खरीदता है और खांडसारी के निर्माण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए गुड़ का उपयोग नहीं करता है, धारा 5 (2) (ए) का दूसरा परंतुक। (ii) पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। उसे गुड़ की खरीद पर बिक्री कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वह उस गुड़ का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करता है जिसके लिए उसे बेचा गया था। यह बिल्कुल अलग बात है कि डीलर निर्माण के लिए कर गुड़ से मुक्त खरीद का हकदार नहीं था। कर-मुक्त वस्तुओं की संख्या जैसे खांडसारी, लेकिन जैसा कि उसने गुड़ का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया, धारा 5(2)(क)(ii) के दूसरे परंतुक का कोई अनुप्रयोग नहीं है। अधिनियम का कोई अन्य प्रावधान नहीं है

जिसके तहत राज्य डीलर को खरीद मूल्य पर कर लगाने के लिए मूल्यांकन कर सकता है। गुड़ जो उसके द्वारा किसके निर्माण के लिए खरीदा गया था, *खांडसारी* पर प्रवर्तन-बिंदु पंजीकरण प्रमाण पत्र और फॉर्म में घोषणा एस. टी. XXII वही बेचने वाला डीलर कटौती का दावा करने का हकदार नहीं हो सकता है बिक्री का कारोबार गुड़ के निर्माण के लिए कर मुक्त बेचा गया *खांडसारी* से उसकी स्थूल टर्नओवर और यदि वह इस तरह की कटौती का दावा करता है, तो इसे मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन खरीद डीलर गुड़ भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता *स्त्री-विषयक* (ग) राज्य सरकार को कर का भुगतान करना क्योंकि विक्रय करने वाला डीलर अपने बिक्री कारोबार पर कर का भुगतान करने के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी है। गुड़/यदि विक्रय करने वाले डीलर ने क्रय विक्रेता से कर वसूलने में चूक की है, तो उसके पास क्रय करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई का कारण हो सकता है, न कि राज्य सरकार के खिलाफ। राज्य सरकार बिक्री डीलर की ओर से कार्य नहीं कर सकती है और धारा के दूसरे परंतुक के प्रावधानों को लागू नहीं कर सकती है 5(2) (क) (ii) क्रय डीलर से बिक्री कर वसूलने के लिए अधिनियम।
(पैरा 8)

माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति डीके महाजन और माननीय न्यायमूर्ति पीसी जैन शामिल थे, द्वारा 9 फरवरी, 1972 को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर राय के लिए एक बड़ी पीठ को मामला भेजा गया। महाजन, माननीय न्यायमूर्ति बाल राज तुली और माननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन की वृहद पीठ ने अंततः 25 अप्रैल, 1972 को मामले का निपटारा कर दिया।

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत इस माननीय उच्च न्यायालय को दिए गए संदर्भ में श्री एसके छिब्बर, बिक्री कर अधिकरण, हरियाणा के न्यायालय के दिनांक 28 नवम्बर, 1969 के आदेश से उत्पन्न कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लिया गया है। आकलन वर्ष 1965-66 के लिए 1969-70 की रिट याचिका सं 55 -

"क्या परिस्थितियों में और मामले के तथ्यों के आधार पर, अधिनियम की

धारा 5 (2) (ए) (ii) के दूसरे परंतुक के प्रावधान को गुड़ के कर खरीद मूल्य (4,50,780.53 रुपये) पर सही तरीके से लागू किया गया था?

संख्या II. क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 100 क्विंटल गुड़ से 38 क्विंटल खंडसारी और 62 क्विंटल शीरा प्राप्त हुआ और अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) (ii) के दूसरे परंतुक के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, गुड़ के खरीद मूल्य के केवल 38 प्रतिशत पर कर लगाया जा सकता है। पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर खरीदा गया और खंडसारी के निर्माण की प्रक्रिया में खपत हुई?"

एम एस जैन, जे.एल. गुप्ता और जी.सी गर्ग . याचिकाकर्ता की ओर से वकील

I

सी. डी. दीवान अतिरिक्त महान्यायविद प्रतिवादी हरियाणा की ओर से।

निर्णय

बी. आर. तुली, न्यायमूर्ति. - यह संदर्भ 9 फरवरी, 1972 को मेरे विद्वान न्यायमूर्ति भाइयों, महाजन और जैन, के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जब याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने हरियाणा राज्य में इस न्यायालय के एक खंडपीठ के फैसले और एक अन्य वीएमएस करनाल गुड़ और खांडसारी इंडस्ट्रीज, चुलकाना रोड, स्मलखा मंडी पर भरोसा किया। जिला करनाल (1)। चूंकि उस निर्णय की शुद्धता पर संदेह किया गया था, इसलिए मामले को पूर्ण न्यायपीठ द्वारा सुनने का निर्देश दिया गया था और इस तरह इस संदर्भ को निर्णय के लिए इस पीठ के समक्ष रखा गया है।

(2) याचिकाकर्ता मेसर्स पंजाब खांडसारी उद्योग, सोनीपत पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत एक डीलर के रूप में पंजीकृत है और इसने वर्ष 1965-66 के दौरान खांडसारी के निर्माण और बिक्री का व्यवसाय किया। 21 अप्रैल, 1965 को मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता को पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसमें यह प्रमाणित किया गया था कि याचिकाकर्ता को अधिनियम के तहत एक डीलर के रूप में पंजीकृत किया गया था, इसका व्यवसाय "खांडसारी का निर्माण" था और गुड़, शकर और खंड और कुछ अन्य सामानों की बिक्री (ए) निर्माण के उद्देश्य से और (बी) पुनर्विक्रय के लिए, कर मुक्त होगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता ने खांडसारी के निर्माण के लिए बिना किसी बिक्री-कर का भुगतान किए गुड़ खरीदा।

(13) वर्ष 1965-66 के लिए अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता का आकलन कर निर्धारण प्राधिकरण रोहतक द्वारा 18 मई, 1968 के आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता विनिर्माण कर रहा था खांडसारी" जो कर-मुक्त सामान है गुड़ खरीदने के बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र के खिलाफ है। इसलिए वह अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) (2) (2) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। आकलन प्राधिकरण की राय थी कि अधिनियम की धारा 7 को धारा 5 (2) (ए) (2) के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "एक डीलर कर मुक्त वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर माल की खरीद करने का हकदार है। धारा 5 और 7 के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करने के बाद, यह माना गया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने खरीद की थी गुड़ के निर्माण के लिए खांडसारी जो की कर मुक्त वस्तुएं थी। यह अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) (ii) के दूसरे परंतुक के तहत बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। गुड़ का मूल्य गुड़ जिसे याचिकाकर्ता द्वारा इसके पंजीकरण प्रमाण पत्र के

खिलाफ खरीदा गया था और इसका उपयोग किसके निर्माण में किया गया था? *खांडसारी* 5,00,741.00 रुपये के रूप में निर्धारित किया गया था, जिस पर 6 प्रतिशत की राशि पर बिक्री-कर, 30,044.46 रुपये का मूल्यांकन किया गया था, मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की जिसमें यह माना गया कि याचिकाकर्ता *खांडसारी* के निर्माण के लिए गुड़ को बिक्री कर का भुगतान किए बिना नहीं खरीद सकता है, लेकिन चूंकि यह *खांडसारी* (कर-मुक्त सामान) और गुड़ (कर योग्य वस्तुएं) दोनों का निर्माण करता है, इसलिए यह गुड़ के खरीद मूल्य पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है । *इसमें खांडसारी* जो केवल 38 प्रतिशत था, शेष 62 प्रतिशत शीरे के लिए जिम्मेदार था। इस प्रकार याचिकाकर्ता को 1,71,296.00 रुपये पर बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, जो 50,074.00 रुपये के बजाय 4,50,780.53 रुपये के रूप में निर्धारित गुड़ के खरीद मूल्य का 38 प्रतिशत था । इस राशि पर 6 प्रतिशत की दर से 10,277.76 रुपये का बिक्री कर लगाया गया। तदनुसार मूल्यांकन के आदेश को संशोधित किया गया और 19 जुलाई, 1968 को अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। आबकारी और कराधान आयुक्त, हरियाणा ने अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत स्वतः कार्रवाई की और याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को संशोधित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की बात सुनने के बाद आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने फैसला किया कि गुड़ के खरीद मूल्य के 38 प्रतिशत पर नहीं बल्कि *प्रत्येक 100 क्विंटल गुड़ में से 38 क्विंटल* *खांडसारी* के बाजार मूल्य पर कर लगाया जाना चाहिए और अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को दरकिनार करते हुए उनके द्वारा बताए गए आधार पर नए सिरे से आकलन के लिए मामले को आकलन प्राधिकरण के पास भेज दिया गया। यह आदेश 9 मई, 1969 को पारित किया गया था, और उस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने बिक्री कर न्यायाधिकरण, हरियाणा के समक्ष अपील दायर की थी। न्यायाधिकरण ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया और आकलन प्राधिकरण द्वारा पारित मूल आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को खरीद की गई गुड़ की पूरी मात्रा के खरीद मूल्य पर कर लगाने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। आकलन प्राधिकरण को उस आधार पर कर की पुनर्गणना करने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश 23 जुलाई, 1969 को पारित किया गया था, और व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने आवेदन में उल्लिखित कानून के कुछ सवालों को इस न्यायालय को संदर्भित करने के लिए अधिनियम की धारा 22 (1) के तहत एक आवेदन दायर किया। विद्वान बिक्री कर न्यायाधिकरण ने 28 नवंबर, 1969 के आदेश द्वारा उस आवेदन को स्वीकार कर लिया और निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को इस न्यायालय को

भेज दिया: -

(i) क्या परिस्थितियों और मामले के तथ्यों के आधार पर, अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) (ii) के दूसरे परंतुक के प्रावधानों को गुड़ के कर खरीद मूल्य (4,780.53 पीएस) पर सही ढंग से लागू किया गया था?

(11) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 100 क्विंटल गुड़ से 38 क्विंटल खांडसारी और 62 क्विंटल की पैदावार हुई?
अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) (2) के दूसरे परंतुक के प्रावधानों के तहत कर के तहत क्विंटल शीरे को पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर खरीदे गए और खांडसारी बनाने की प्रक्रिया में खपत किए गए गुड़ पर खरीदे गए मूल्य के केवल 38 प्रतिशत पर लगाया जा सकता है।

(4) यह मामला 8 जनवरी, 1970 को न्यायमूर्ति महाजन और संधावालिया, के समक्ष सुनवाई के लिए आया और इसे इस न्यायालय के संदर्भ के लिए मामले का उचित विवरण तैयार करने के लिए ट्रिब्यूनल को वापस कर दिया गया। नतीजतन ट्रिब्यूनल ने 10 अगस्त, 1970 को मामले का एक नया बयान प्रस्तुत किया।

(5) हमारे सामने याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि खांडसारी कर-मुक्त सामान नहीं है क्योंकि यह अधिनियम की अनुसूची बी में प्रविष्टि 62 के अर्थ के भीतर 'चीनी' नहीं है और इस प्रकार पंजीकरण प्रमाण पत्र का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। लेकिन विभागीय अधिकारियों के समक्ष, यह दोनों पक्षों का सामान्य मामला था कि खांडसारी को 'चीनी' शब्द में शामिल किया गया था और बिक्री कर के भुगतान से छूट दी गई थी और खांडसारी के बिक्री कारोबार पर कोई कर नहीं लगाया गया था। इसलिए, इस तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि खांडसारी कर योग्य सामान है और कर-मुक्त सामान नहीं है और याचिकाकर्ता द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया था।

(6) अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) (ii), जैसा कि 1965-66 में लागू था, निम्नानुसार पढ़ा गया: -

"5(2) इस अधिनियम में 'कर योग्य कारोबार' से अभिप्रेत है किसी भी अवधि के दौरान डीलर के सकल कारोबार का वह हिस्सा जो उसमें से कटौती के बाद शेष रहता है-

(क) उक्त अवधि के दौरान उनका कारोबार कितना था?

(1) धारा 6 के तहत माल की बिक्री को कर-मुक्त घोषित किया गया;

(2) उपधारा (आई-ए) के तहत पहले चरण में कर के अधीन वस्तुओं की बिक्री के अलावा अन्य वस्तुओं के पंजीकृत डीलर को बिक्री जो उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पंजाब राज्य में पुनर्विक्रय के लिए अभिप्रेत है या अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री या भारत के क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के दौरान बिक्री या उपयोग के लिए उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री के लिए है। पंजाब में निर्माण में उनके द्वारा

धारा 6 के तहत कर-मुक्त घोषित वस्तुओं के अलावा किसी भी सामान को पंजाब में बिक्री के लिए और ऐसे सामानों की पैकिंग के लिए कंटेनर या अन्य सामग्रियों के पंजीकृत डीलर को बिक्री पर:

बशर्ते कि ऐसी बिक्री के मामले में, पंजीकृत डीलर द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित एक घोषणा, जिसे माल और बेचा गया था और ^ निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त एक निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित विवरण शामिल है, उस डीलर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो माल बेचता है:

परन्तु जब ऐसे माल का उपयोग उस डीलर द्वारा किया जाता है जिसे ये उन प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए बेचे जाते हैं जिनके लिए ये उसे बेचे गए थे, तो वह ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर लगाए गए कर की दर से अधिक नहीं होने पर उस दर पर खरीद पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट डीलरों के वर्ग के संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे, इसके बावजूद कि ऐसी खरीद धारा 2 के खंड (एफएफ) द्वारा कवर नहीं की जाती है।

(7) अधिनियम के खंड 7 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं; डीलरों का पंजीकरण अनुपात जिसके अनुसार अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई भी डीलर डीलर के रूप में व्यवसाय नहीं कर सकता है जब तक कि वह पंजीकृत न हो और उसके पास पंजीकरण प्रमाण पत्र न हो। पंजाब सामान्य बिक्री कर नियम, 1949 का नियम 26, अधिनियम की धारा 6 (2) (ए) (ii) में उल्लिखित मामले से संबंधित है और 1965-66 में निम्नानुसार पढ़ा गया है: -

"एक डीलर, जो अपने सकल कारोबार से बिक्री के संबंध में राशि को इस आधार पर घटाना चाहता है कि वह अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड

(ए) के उप-खंड (ii) के प्रावधानों के तहत इस तरह की कटौती करने का हकदार है, मांग पर, ऐसी डब्ल्यू बिक्री के संबंध में संबंधित कैश मेमो या बिल की प्रति प्रस्तुत करेगा। चूंकि बिक्री नकद बिक्री या उधार पर बिक्री है, और खरीदने वाले डीलर या उसके एजेंट द्वारा फॉर्म एसटी एक्सएक्सआई में लिखित रूप में एक घोषणा की गई है कि विचाराधीन सामान पंजाब राज्य में पुनर्विक्रय के लिए है या ऐसे सामान पंजाब राज्य में बिक्री के लिए पंजाब राज्य में निर्माण में उसके द्वारा उपयोग के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट किए गए हैं।

नियम 26 में उल्लिखित फॉर्म एस.टी. XXII, जैसा कि निर्धारित किया गया है, निम्नलिखित शर्तों में था: -

"फॉर्म एस.टी. XXII.

किसी पंजीकृत डीलर द्वारा किसी अन्य पंजीकृत डीलर से माल खरीदने के लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना (पंजाब सामान्य बिक्री कर नियम, 1949 के नियम 26 और 27-ए देखें)। मैं धारक सत्यापन प्रमाण पत्र संख्या..... इसके द्वारा घोषणा की जाती है कि मेरे इसके बाद उल्लिखित माल निम्नलिखित के लिए खरीदा गया है :-

- (1) बिक्री के लिए किसी भी सामान के पंजाब राज्य में निर्माण में उपयोग;
- (2) पंजाब राज्य में पुनर्विक्रय; नहीं तो
- (3) अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री; नहीं तो
- (4) भारत के क्षेत्र से बाहर निर्यात के दौरान बिक्री;

और ऊपर (1) में उल्लिखित उद्देश्य के लिए खरीदे गए सामान पूरी तरह से मेरे पूर्वोक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट हैं।

विवरण मात्रा, मूल्य, संख्या और तिथि: माल के पूर्ण हस्ताक्षर कैश मेमो या बिक्री डीलर

विक्रय पंजीकृत डीलर द्वारा जारी किया गया बिल

पूर्ण हस्ताक्षर और पूर्ण

स्थान डीलर का पता या

Dalte उसका अधिकृत एजेंट।

कर्तन

(8) अधिनियम की धारा (5(2)(क)(ii) h अधिनियम को सामान्य बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम संख्या 2) द्वारा संशोधित किया गया ताकि धारा 6 के तहत कर-मुक्त घोषित वस्तुओं के अलावा अन्य शब्द सम्मिलित किए जा सकें जो पहले नहीं थे। वह अधिनियम आया था।

23 मार्च, 1963 से लागू हुआ, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 21 अप्रैल, 1965 को याचिकाकर्ता को पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने वाले आकलन प्राधिकरण, रोहतक को 1963 के पंजाब अधिनियम 2 द्वारा किए गए संशोधन के बारे में पता नहीं था, और यही कारण है कि पंजीकरण के इस प्रमाण पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को कर मुक्त खरीद की अनुमति दी गई थी। *गुर, शकर* और *खांड* और निर्माण के लिए कुछ अन्य सामान *खांडसारी*, जो उप-धारा के खंड (ए) के संशोधित स्टब-खंड (ii) के तहत अनुमेय नहीं था। (2) अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, या तो कर निर्धारण प्राधिकारी ने विचार नहीं किया *खांडसारी* - \wedge चीनी होना और इसलिए, अधिनियम की अनुसूची बी में प्रविष्टि संख्या 62 के तहत कर-मुक्त होना या संशोधन उनकी जानकारी में नहीं था। इस संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए नियम 26 और एसटी XXII में भी संशोधन नहीं किया गया था, जब तक कि पंजाब सरकार ने 8/10 अक्टूबर, 1966 को अधिसूचना जारी नहीं की, ताकि पंजाब में बिक्री के लिए धारा 6 के तहत कर मुक्त घोषित वस्तुओं के अलावा किसी भी सामान के पंजाब में निर्माण में उपयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रतिस्थापित किया जा सके। "एस.टी. वीएक्सआई से। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता द्वारा बिक्री करने वाले डीलरों को प्रस्तुत की गई घोषणाएं, 10 अक्टूबर, 1966 से प्रभावी इसके संशोधन से पहले फॉर्म एसटी एक्सएक्सआईआई में थीं। यदि, जैसा कि तर्क दिया गया है, याचिकाकर्ता खरीद का हकदार नहीं था *गुड़* 1965-66 में अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) के संशोधित खंड (ii) के मद्देनजर अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर कर मुक्त, विक्रेता को समान रूप से खुद को संतुष्ट करना चाहिए था कि क्या याचिकाकर्ता खरीद का हकदार था। *गुड़* के निर्माण के लिए *खांडसारी* 1965-66 में यथा संशोधित और लागू अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) (ii) के प्रावधानों के तहत, इसके पंजीकरण प्रमाण पत्र में प्रविष्टि पर ध्यान दिए बिना। उसे बेचने से मना कर देना चाहिए था। *गुड़* के निर्माण के लिए याचिकाकर्ता को कर से मुक्त *खांडसारी* जो कर मुक्त वस्तुएं थीं। याचिकाकर्ता ने नहीं किया इस्तेमाल *गुड़* के निर्माण के लिए खरीदा गया *खांड- साड़ी* पंजीकरण के अपने प्रमाण पत्र और बिक्री डीलर (डीलरों) को प्रस्तुत घोषणाओं के आधार पर,

निर्माण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए *खांडसारी*। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि ऊपर उल्लिखित धारा 5 (2) (ए) (ii) के दूसरे परंतुक के बिना, याचिकाकर्ता को खरीद पर कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। *गुड़* क्योंकि यह इसका इस्तेमाल नहीं किया। *गुड़* किसी भी उद्देश्य के लिए अन्य उस से अधिक जिसके लिए इसे बेचा गया था। यह बिल्कुल अलग बात है कि याचिकाकर्ता खरीद के लिए € का हकदार नहीं था

खांडसारी जैसे *कर-मुक्त माल के निर्माण* के लिए कर से मुक्त *गुड़* लेकिन *इसने* किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस *गुड़* का उपयोग नहीं किया। दोहराने के लिए, *गुड़* *खांडसारी* के *निर्माण के लिए खरीदा गया था* और इसका उपयोग किया गया था। इसी उद्देश्य के लिए। धारा 5 (2) (ए) (ii) के दूसरे परंतुक में, इसलिए, अधिनियम का कोई आवेदन और कोई अन्य प्रावधान हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है, जिसके तहत राज्य याचिकाकर्ता को *खण्डसारी* के निर्माण के लिए खरीदे गए *गुड़* के purchs.se मूल्य पर कर लगाने के लिए मूल्यांकन कर सकता है। यह स्पष्ट है कि 1965-66 में संशोधित और लागू धारा 3 (2) (ए) (ii) के तहत, बिक्री डीलर याचिकाकर्ता को *बेचे गए गुड़* के बिक्री कारोबार के लिए अपने सकल कारोबार से *खांडसारी के निर्माण के लिए कर-मुक्त* बिक्री कारोबार के लिए कटौती का दावा करने का हकदार नहीं था और यदि दावा किया जाता है, तो आकलन प्राधिकरण को इसे अस्वीकार कर देना चाहिए था। यदि बिक्री करने वाले डीलर को उस कटौती की अनुमति दी गई है, तो यह केवल इस आधार पर हो सकता है कि *खांडसारी* कर-मुक्त सामान नहीं है। यदि ऐसा है, तो याचिकाकर्ता के हाथों में *खांडसारी* पर एक अलग व्याख्या नहीं रखी जा सकती है। उस आधार पर, याचिकाकर्ता *गुड़* की खरीद पर किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है / किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो याचिकाकर्ता को *गुड़* के खरीद मूल्य पर राज्य सरकार को कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है *क्योंकि सरकार के लिए बिक्री डीलर गुड़ के अपने बिक्री कारोबार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है* और यदि वह याचिकाकर्ता से कर एकत्र करने में विफल रहता है, उनके पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का कारण हो सकता है लेकिन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं। राज्य सरकार विक्रेता की ओर से कार्य नहीं कर सकती है, जो स्वयं एक करदाता है, लेकिन मूल्यांकन प्राधिकारी याचिकाकर्ता को *गुड़* की बिक्री के संबंध में धारा 5 (2) (ए) (ii) के तहत दावा किए जाने पर उसके बिक्री कारोबार से किसी भी कटौती को अस्वीकार कर सकता है।

(9) इस मामले पर मैंने कमल गुर और *खांडसारी इंडस्ट्रीज बनाम भारत* में विचार किया था। *हरियाणा राज्य और दूसरा* (2), जो *फैंसी नेट और फैब्रिक्स के परिशिष्ट के रूप में मुद्रित है। पंजाब राज्य और दूसरा* (3)। उस मामले में याचिकाकर्ता

को 3 जून, 1965 को पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता फर्म *गुड़, खांडसारी, बरदाना आदि में एक डीलर थी।* और खांडसारी और *गुर-शीरा* का निर्माण और गुड़ आदि के निर्माण के उद्देश्य से *गुड़, जलाऊ लकड़ी, सज्जी* और चूने को कर मुक्त पुनर्विक्रय के लिए खरीदने का *हकदार था*। उस प्रमाण पत्र के आधार पर, याचिकाकर्ता फर्म ने *गुड़* और अन्य सामान खरीदे, जिनमें से कुछ को फिर से बेच दिया गया और अन्य का उपयोग *आकलन वर्ष 1965-66 के दौरान* खांडसारी और *गुड़-शीरा* के निर्माण में किया गया।

(2) 1968 के सी. डब्ल्यू. संख्या 1287 ने 10 फरवरी, 1970 को निर्णय लिया।

(3) (1971) 28 एस.टी.सी.

1 अप्रैल, 1965 से 31 मार्च, 1966)। उस वर्ष के लिए याचिकाकर्ता ने त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत किया और उन रिटर्न के अनुसार कर का भुगतान किया। आकलन प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता-फर्म को अधिनियम की धारा 11 (2) और 14 के तहत मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए नोटिस जारी किया और उन्हें 20 मार्च, 1968 को गुड़ और खातों आदि की खरीद के बारे में विवरण के साथ पेश होने के लिए कहा। आकलन प्राधिकरण का मानना था कि याचिकाकर्ता-फर्म अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) (2) के दूसरे परंतुक के तहत *खांडसारी* के निर्माण के लिए उसके द्वारा की गई *गुड़* की खरीद पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार उस मामले के तथ्य इस मामले के तथ्यों के समान थे और उन तथ्यों पर मैंने निम्नानुसार देखा: -

पीठ ने कहा, "लिखित बयान में प्रतिवादियों का मामला नहीं है और न ही आकलन प्राधिकारी ने आकलन के आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता-फर्म ने किसी अन्य मुद्रा के लिए गुड़ खरीदा और खांडसारी के निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल किया / पंजीकरण प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता-फर्म को *खांडसारी* और *गुड़-शीरा* के निर्माण के लिए *गुड़* को कर मुक्त खरीदने का अधिकार देता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता-फर्म ने *खांडसारी* और *गुर-शीरा* के निर्माण के लिए खरीदे गए *गुड़* का इस्तेमाल उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया, जिसके लिए इसे बेचा गया था। इस प्रकार याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया था, जब उसने पंजीकरण प्रमाण पत्र के बल पर *खांडसारी* और *गुड़-शीरा* के निर्माण के लिए कर मुक्त *गुड़* खरीदा था। इस प्रकार अधिनियम की धारा 5 (2) (ए)

(ii) के परंतुक में इस मामले के लिए कोई प्रयोज्यता नहीं है। डीलर या डीलर, जिन्होंने *खांडसारी* और *गुड़-शीरा* के निर्माण के लिए इस पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता-फर्म को *गुड़* बेचा। अपने सकल कारोबार से कटौती करने का हकदार नहीं हो सकता है क्योंकि *खांडसारी* एक कर-मुक्त माल है, लेकिन याचिकाकर्ता को उस *गुड़* की खरीद पर बिक्री कर के भुगतान के लिए बिक्री कर विभाग के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है /विक्रेता के लिए यह खुला था कि वह क्रेता, अर्थात् याचिकाकर्ता से इसकी वसूली करे, लेकिन यह विभाग के लिए खुला नहीं है कि वह क्रेता से इसकी वसूली करे क्योंकि अधिनियम के तहत, यह केवल विक्रेता द्वारा देय है। इसलिए 1,31,522.31 रुपये की राशि पर 6 प्रतिशत की दर से बिक्री कर लगाया जाना रद्द किया जाना चाहिए।

(10) इस फैसले के खिलाफ हरियाणा राज्य के 10वें पत्र के खंड ग के तहत एक और याचिका दायर की गई है। एमएफएस करनाल *गुड़* और *खांडसारी इंडस्ट्रीज, चुलकाना रोड, समालखा मंडी जिला करनाल* (1) दायर किया गया था जिसे एक खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसने मेरे द्वारा की गई उपर्युक्त टिप्पणियों की स्पष्ट रूप से पुष्टि की थी। मेरे निर्णय को इस न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ द्वारा भी अनुमोदित किया गया था, जिसमें महाजन और गोपाल सिंह, जेजे शामिल थे। *पंजाब राज्य और दूसरा* (3) (सुप्रा)। हमें यह मानने के लिए प्रेरित नहीं किया गया है कि उन निर्णयों ने मामले को सही ढंग से तय नहीं किया है और सम्मान के साथ हम इसकी पुष्टि करते हैं।

(11) उत्तरदाताओं के वकील ने मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम *बिक्री कर आयुक्त, पंजाब* (4) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया है, जो तथ्यों पर काफी अलग है। उस मामले में, मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड एक पंजीकृत डीलर थी और अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर कच्चा कपास खरीदा और पंजाब में अपनी जिनिंग मिलों में गिनने के बाद, गांठों को कपड़े के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी बुनाई मिलों में भेज दिया। अपने कर योग्य कारोबार की गणना करते हुए, निर्धारिती ने दावा किया कि कपास की खरीद अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) (ii) के तहत कर मुक्त थी क्योंकि उसे दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र में कोई शर्त नहीं थी कि प्रमाण पत्र के तहत खरीदी गई कपास को पंजाब राज्य में निर्माण के अधीन किया जाना चाहिए। प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद, अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) (ii) और पंजाब सामान्य बिक्री कर नियम, 1949 के नियम 26 में उस शर्त को प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था। उन तथ्यों

के आधार पर यह माना गया कि पंजीकरण प्रमाण पत्र केवल इस बात का सबूत था कि निर्धारित निर्माण में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुओं के प्रयोजनों के लिए एक पंजीकृत डीलर था, उनमें से एक कपास था। पुराना पंजीकरण प्रमाण पत्र, भले ही इसमें "पंजाब राज्य में" शब्द शामिल नहीं थे, अनुभागों, नियम और फॉर्म द्वारा एक साथ संचालित किया जाएगा। करदाता को अधिनियम और नियमों का पालन करना था और वह असंशोधित प्रमाण पत्र के पीछे शरण नहीं ले सकता था। उस मामले में करदाता कंपनी ने अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) (ii) के तहत अपने सकल कारोबार में से कटौती का दावा किया, जिसे निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अस्वीकार कर दिया गया था: -

"इसमें तीन शर्तें शामिल हैं: पहला यह है कि वे डीलर के उपयोग के लिए होना चाहिए! दूसरा यह है कि उन्हें पंजाब राज्य में विनिर्माण के लिए होना चाहिए: और तीसरा यह है कि विनिर्माण के परिणामस्वरूप बिक्री के लिए सामान होना चाहिए। यह तय करना आवश्यक नहीं है कि बिक्री होनी चाहिए या नहीं

इस कारण से पंजाब में भी रहें कि आवश्यकतानुसार कोई बिक्री नहीं हुई। छूट का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब कंपनी सभी तीन शर्तों को पूरा करती है। इस मामले में अंतिम शर्त पूरी होती नहीं दिख रही है। "बिक्री के लिए" शब्द माल की गुणवत्ता को दर्शाता है और यह स्पष्ट है कि पंजाब में निर्मित माल बिक्री के लिए होना चाहिए। धारा के अनुसार जो सामान निर्माण का परिणाम है, वह बिक्री के लिए होना चाहिए, न कि निर्माता द्वारा राज्य के बाहर कुछ निर्माण में उपयोग के लिए जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सामान होते हैं। पंजाब राज्य में कंपनी द्वारा निर्मित माल जिन्ड कपास की गांठें थीं और वे बिक्री के लिए नहीं थे क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश में इसकी कटाई और बुनाई मिलों में भेजा गया था। इसलिए इस छूट का दावा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा सकता कि धारा की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था।

(12) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) (ii) के तहत किसी भी कटौती का दावा नहीं कर रहा है, लेकिन कर का भुगतान करने के लिए अपनी देयता का विरोध कर रहा है जो अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) के खंड (ii) के दूसरे परंतुक के तहत लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि 1964 के अधिनियम 2 द्वारा अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) (ii) में किए गए संशोधन के आधार पर, याचिकाकर्ता *खांडसारी* के निर्माता के लिए उसके प्रमाण पत्र के आधार पर कर से मुक्त गुड़ नहीं खरीद सकता था, जिसे आकलन प्राधिकरण

द्वारा गलत तरीके से जारी किया गया था। इस मामले को देखते हुए, विक्रेता डीलर/डीलरों को याचिकाकर्ता को कर मुक्त गुड़ नहीं बेचना चाहिए *था* क्योंकि उन्हें भी याचिकाकर्ता के रूप में कानून की जानकारी होने का अनुमान था। *फैंसी नेट्स एंड फैब्रिक्स केस (3) (ऊपर लिखित) के तथ्य मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स केस (4) (ऊपर लिखित) के तथ्यों के समान थे* और उस मामले पर फैसला करते समय बेंच ने मेरे फैसले को मंजूरी दे दी जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है।

(13) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, प्रश्न संख्या 10 का हमारा उत्तर नकारात्मक है, अर्थात् करदाता के पक्ष में और विभाग के खिलाफ है। इस मामले के इस दृष्टिकोण में प्रश्न संख्या 2 नहीं उठता है और इसलिए कोई उत्तर नहीं दिया जाता है। चूंकि मामला कठिनाई से मुक्त नहीं था, इसलिए हम पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आकाश सरोहा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी, हरियाणा